डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 जुलाई, 2022, डिस्पेच दिनांक 1 जुलाई, 2022

| वर्ष 66 | अंक 03 | भोपाल | 1 जुलाई, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

वर्तमान प्रतिस्पर्द्धा की दौड़ में सहकारी बैंकों को बेहतर साबित करना होगा - के.सी.गुप्ता, प्रमुख सचिव, सहकारिता

आधुनिक तकनीकी को अपनाकर सहकारी बैंक प्रगति पथ पर अग्रसर हों - संजय गुप्ता, आयुक्त सहकारिता एवं प्रशासक, अपेक्स बैंक

भोपाल। मध्यप्रदेश के 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं अपेक्स बैंक के संभागीय शाखा प्रबंधकों की भोपाल के टी.टी.नगर स्थित अपेक्स बैंक मुख्यालय के समन्वय भवन के सभागार में प्रमुख सचिव, सहकारिता श्री के. सी.गुप्ता, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें एवं प्रशासक, अपेक्स बैंक श्री संजय गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित बैठक में श्री गुप्ता ने निर्देशित किया कि हमारी अनेक योजनायें राष्ट्रीयकृत बैंकों से बेहतर हैं, लेकिन समुचित प्रचार–प्रसार, ब्रांडिंग, व्यवसायिक कार्यदक्षता में निपुणता का अभाव एवं उचित विपणन व्यवस्था न हो पाने की वजह से हमारे प्रादेशिक/जिला सहकारी बैंक अपने व्यवसाय के संवर्द्धन में कारगर प्रयास कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ''जीरो'' प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, सभी प्रकार के ऋण शासकीय कर्मचारियों को मात्र 8 प्रतिशत ब्याज दर उपलब्ध कराना, सीबीएस के माध्यम से बैंकिंग का संचालन करना, सस्ते दरों पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराना जैसी अनेक योजनाएं हैं, जो वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में सहकारी बैंकों द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिन्हें उचित प्रबंधन व्यवस्था के माध्यम से प्रचार–प्रसार के आधुनिक संसाधनों यथा – व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, पेम्पलेट, ब्रोशर एवं व्यक्तिगत सम्पर्क करके सहकारी बैंकों के कार्य–व्यवसाय को बढ़ाने की दिशा में सतत् प्रयास किये जायें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सहकारी उचित मूल्य की दुकानों को भी आकर्षक बनाया जावे।

इस अवसर पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें एवं प्रशासक, अपेक्स बैंक श्री संजय गुप्ता ने भी इस बात पर जोर दिया कि सूचना तकनीक के स्त्रोतों के माध्यम से प्रदेश की अपेक्स बैंक की सभी शाखायें एवं जिला बैंक कार्य संचालित कर रहे हैं, अतः और कैसे हम अपने आधुनिक संसाधनों के माध्यम से इनका बेहतर उपयोग करते हुए अपने बैंकों को प्रगति पथ पर अपने कर्मठ प्रयासों से अग्रसर करने की दिशा में सफल हो, यह सभी की जिम्मेदारी है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

आजादी के अमृत महोत्सव में पूरा मध्यप्रदेश हुआ योगमय

ग्रामीणों में भी दिखा योगासन के प्रति उत्साह
अमृत सरोवर के तट, पर्यटन और पुरातत्व स्थलों पर हुआ सामूहिक योग
मुख्यमंत्री, केन्द्रीय और राज्य के मंत्रियों ने भी नागरिकों के साथ किया योग
मानवता के लिये योग थीम पर सभी वर्गों ने की सहभागिता

भोपाल: आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस वर्ष 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की, वही केन्द्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के मंत्रीगण भी विभिन्न जिलों में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायतों में भी छात्र-छात्राओं, ग्रामीणजन, महिला स्व-सहायता समूह सहित मनरेगा के श्रमिकों ने कार्य स्थल और अमृत सरोवर के तटों पर सामूहिक योग किया। प्रदेश के पुरातत्व और पर्यटन स्थलों पर भी जन-प्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने मानवता के लिये योग थीम पर योगाभ्यास किया।

मुरैना जिले के प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल बटेश्वर मंदिर समूह में केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार, ग्वालियर किले के पुरातत्व स्थल पर केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विश्व प्रसिद्ध

(शेष पृष्ठ 6 पर)

प्रदेश में टैक्स के आधार को विस्तृत करने निरंतर प्रयासरत रहें–मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए दी बधाई

लोगों को राजस्व राशियाँ और विभिन्न कर जमा करने के लिए निरंतर प्रेरित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों के अधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि व्यवस्था में सुधार, तकनीक के प्रयोग और लोगों को राजस्व एवं कर की राशि जमा करने के लिए निरंतर प्रेरित करने के परिणामस्वरूप ही राज्य में लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्तियाँ संभव हुई है। हमें प्रदेश में टैक्स के आधार को विस्तृत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है। साथ ही व्यवस्था में विद्यमान गैप्स को चिन्हित कर उनमें सुधार के प्रयास लगातार जारी रहे। प्रदेश में विकास गतिविधियों का संचालन और जन-कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत सीमा तक विभिन्न करों और राजस्व से प्राप्त राशि पर निर्भर है। अतः हमें, लोगों को राजस्व राशियाँ और विभिन्न कर जमा कराने के लिए निरंतर प्रेरित करना होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय में राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, एसीएस वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थे। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने बैठक में वर्चुअल सहभागिता की। संबंधित विभागों के अधिकारी भी बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि करों की वसूली में लगे अधिकारी-कर्मचारी ईमानदारी और संवेदनशीलता से कार्य करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि कर वसूली के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जाए। भूल-चूक में कर नहीं भरने अथवा कम राशि जमा करने वाले मामलों में सहयोगात्मक और मार्गदर्शी दृष्टिकोण अपनाकर बकाया राशि जमा कराई जाए। जहाँ आवश्यकता हो और मंशा गलत हो, वहाँ निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खनिज राजस्व की पुरानी बकाया राशि की वसूली के लिए समाधान योजना पुन: लागू करने के प्रस्ताव पर सहमति दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सिंचाई के लिए जल दर लेने की प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जाए।

बैठक में वेट, जीएसटी, आबकारी, खनिज, परिवहन, ऊर्जा, वन, राजस्व, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और सिंचाई से हुई प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत किया गया। जानकारी दी गई कि अप्रैल और मई माह के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 7% अधिक प्राप्तियाँ हुई हैं। प्रवर्तन कार्यवाहियों में डाटा विश्लेषण के अधिक से अधिक उपयोग का लाभ हुआ है। स्क्रूटनी के प्रकरणों में भी अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए, परिणामस्वरूप जमा राशि में बढ़ोत्तरी हुई है। जीएसटी के प्रकरणों में भी डाटा एनालेटिक्स तथा रिटर्न्स के आधार पर कमियाँ चिन्हित कर कार्यवाही की गई। रिटर्न फाईल नहीं करने वाले पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें रिटर्न फाईल करने के लिए मैसेजिंग आदि से प्रेरित किया जा रहा है।

जानकारी दी गई कि मोटरयान कर अपवंचन के मामालों में वाहन पोर्टल प्रभावी है। साथ ही राजस्व विभाग में व्यवस्था और प्रक्रियाओं में सुधार के परिणामस्वरूप डायवर्जन और नजूल पट्टे के प्रीमियम के भू-भाटक की वसूली की प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी हुई है।

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल द्वारा ब्याज दरों का पुनर्निधारण किया

अपेक्स बैंक ने सावधि जमा पर बढ़ाई ब्याज दरें – अब 6.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष

भोपाल, अपेक्स बैंक ने बैंक की आल्को कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयानुसार सावधि/ आवर्ति निक्षेप पर अपनी ब्याज दरें दिनॉक 24 जून, 2022 से बढ़ाने के आदेश बैंक के प्रशासक श्री संजय गुप्ता के मार्गदर्शन में बैंक के प्रबंध संचालक श्री पी. एस.तिवारी ने जारी कर दिये हैं । अपेक्स बैंक द्वारा प्रदेश में समस्त 24 शाखाओं में जमा ग्राहकों की सावधि जमा पर अब 3 वर्ष एवं अधिक तक, लेकिन 5 वर्ष से कम पर 6.25 प्रतिशत की दर से ब्याज का निर्धारण दिनॉक 24 जून, 2022 से किया जावेगा, जो कि पूर्व में 5.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष था। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिया जायेगा

बैंक ने यह भी निर्णय लिया है कि बैंक के सभी सम्माननीय वरिष्ठ नागरिक सदस्यों को उनकी सावधि जमा पर उक्त ब्याज दर से अधिक 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर अर्थात् 7.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान भी दिनॉक 24 जून, 2022 से आकलित किया जावेगा।

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक की आल्को कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयानुसार सावधि/ आवर्ती निक्षेप पर समयावधिवार देय ब्याज दरों का दिनांक 24.6.2022 से निम्नानुसार पुनर्निधारण किया है :–

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

क्र	सावधि जमा निक्षेप समयावधि	दिनांक 24.06.2022 से प्रभावशील ब्याज दरें	
		रू.1.00 करोड़ से कम	रू.1.00 करोड़ एवं उससे अधिक
1.	07 दिन से 14 दिन तक	4.10	4.10
2.	15 दिन से 45 दिन तक	4.10	4.10
3.	46 से 90 दिन तक	4.25	4.25
4	91 दिन से 179 दिन तक	4.75	4.75
5.	180 दिन से एक वर्ष से कम तक	5.25	5.25
6.	एक वर्ष एवं अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम तक	6.00	6.00
7.	तीन वर्ष एवं अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम	6.25	6.25
8.	पांच वर्ष एवं उससे अधिक	6.25	6.25

योजना निर्माण और क्रियान्वयन का प्रभावी साधन है पी.एम. गतिशक्ति : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मैदानी स्तर के अधिकारियों का पी.एम. गतिशक्ति से करें ओरिएंटेशन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की पी.एम. गतिशक्ति की समीक्षा

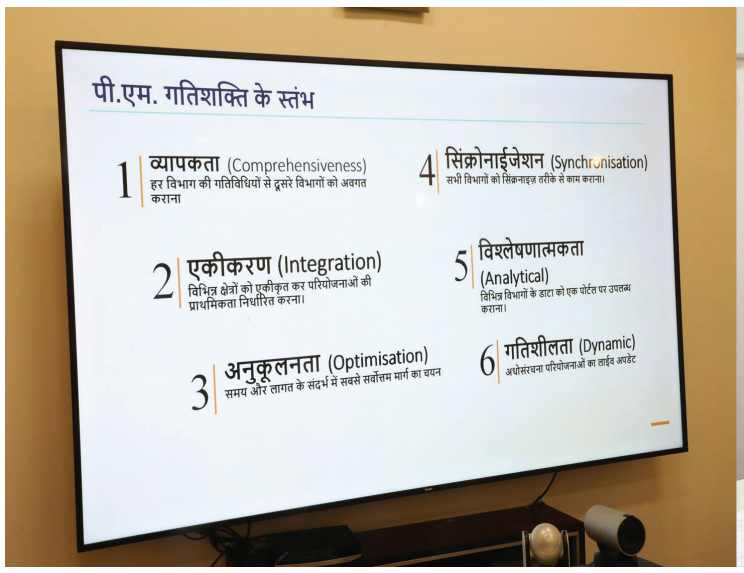

भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पी.एम. गतिशक्ति, योजना निर्माण और क्रियान्वयन का प्रभावी साधन है। इसके प्रभावी उपयोग से समय की बचत के साथ योजनाओं का बेहतर और मितव्ययी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। प्रदेश में मैदानी स्तर तक अधिकारी-कर्मचारियों का पी.एम. गतिशक्ति से ओरिएंटेशन सुनिश्चित किया जाए। पी.एम. गतिशक्ति में प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी अथवा डाटा को जोड़ने की आवश्यकता हो तो उसकी समय-सीमा में पूर्ति सुनिश्चित करें। राज्य का विकास किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय में पी.एम. गतिशक्ति मध्यप्रदेश की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, श्री विनोद कुमार, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, श्री संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्री अमित राठौर, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, श्री नंद कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए अक्टूबर 2021 में पी.एम. गतिशक्ति का शुभारंभ किया गया। इसमें देश में एकीकृत योजना और बुनियादी ढाँचे की कनेक्टिविटी के समन्वित कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार के 16 मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सम्मिलित किया गया है। देश के व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने टेक्सटाईल क्लस्टर, फार्मास्युटिकल क्लस्टर जैसे आर्थिक जोन भी इसमें सम्मिलित हैं। इससे अधो-संरचना से संबंधित योजनाओं में मंत्रालयीन और विभागीय स्तर तक समन्वय और सहयोग बढ़ेगा। साथ ही विकास योजनाएँ तैयार करने के तरीकों में बड़ा बदलाव आएगा। संसाधनों और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा।

कार्य-क्षमता में वृद्धि, समय का सद्उपयोग सुनिश्चित होने के साथ कार्य में दोहराव की संभावनाओं को भी रोका जा सकेगा।

प्रदेश में पी.एम. गतिशक्ति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप गठित किया गया है। इसमें अधो-संरचना से जुड़े मंत्रालयों और विभाग के अधिकारी शामिल हैं। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों को शामिल कर टेक्निकल सपोर्ट यूनिट का गठन किया जा रहा है। पी.एम. गतिशक्ति में मुख्य रूप से सड़क, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, नगरीय विकास एवं आवास और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों में समग्र बुनियादी ढाँचे को सशक्त करने और बेहतर समन्वय के लिए व्यवस्था विकसित होगी।

प्रदेश के विभिन्न विभागों के 27 अधिकारी, गांधी नगर गुजरात के भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एण्ड जियो इन्फॉरमेटिक्स में हुए प्रशिक्षण में शामिल हुए। इनके द्वारा राज्य में विभिन्न स्तरों पर क्षमता विकास गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। प्रदेश में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग पी.एम. गतिशक्ति का नोडल विभाग है।

विद्यार्थियों को जाति और मूल निवासी प्रमाण-पत्र विद्यालय में ही प्राप्त हों : मुख्यमंत्री श्री चौहान

आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने ग्राम स्तर पर चलेगा अभियान

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने को कहा है जिसमें मूल निवासी और जाति प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी अभिलेखों के लिए लोगों को शासकीय कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। मुख्यमंत्री ने पात्र विद्यार्थियों को जाति और मूल निवासी प्रमाण-पत्र विद्यालय में ही दिये जाने को भी सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान सिंगल सिटीजन डेटाबेस पर निवास कार्यालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी लोगों के आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए ग्राम स्तर पर अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रदेशवासियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है और जो शेष रहे हैं, उनकी जानकारी एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं, कमियों और हितग्राहियों की परेशानियों को चिन्हित करने की व्यवस्था भी विकसित करें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, मुख्य सचिव, श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन, श्री विनोद कुमार, प्रमुख सचिव, वित्त, श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्री अमित राठौर, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, श्री नंद कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बताया गया कि विभिन्न विभागों के डेटाबेस को समग्र में शामिल कर एकल नागरिक डेटाबेस का निर्माण करना सिंगल सिटीजन डेटाबेस का मूल उद्देश्य है। अभियान से समग्र में पंजीकृत नागरिकों का ई-केवायसी किया जाएगा। इससे एक समग्र सदस्य को प्राप्त विभिन्न योजनाओं के लाभ की जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। समग्र को सक्षम कर इससे विभिन्न विभागों की सेवाएँ जैसे लाड़ली लक्ष्मी योजना का पंजीयन, जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन आदि दी जा सकेगी। विभिन्न विभागों के डेटाबेस को समग्र में शामिल करने के उद्देश्य से समग्र में आधार संदर्भ संख्या, जाति एवं मूल निवासी प्रमाण-पत्र, भूमि संबंधी जानकारी का विवरण और कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची को जोड़ा जा रहा है। अब तक लगभग 48 लाख जाति प्रमाण-पत्र की समग्र के साथ मेपिंग पूर्ण हो गई है।

बैठक में विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं में समग्र का उपयोग सुनिश्चित करने, विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एकल फार्म बनाए जाने, एक स्तर के सक्षम 2अधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों की सेवाओं को प्रदान करने का अधिकार देने और विवाह प्रमाण-पत्र बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को समग्र पोर्टल पर विकसित करने पर विचार-विमर्श हुआ।

मत्स्याखेट, विक्रय व परिवहन पर 16 जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंध

भोपाल । मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3(2) के अंतर्गत 16 जून 15 अगस्त 2022 तक की अवधि में मत्स्याखेट निषेध किया गया है। इस दौरान मत्स्याखेट की रोकधाम मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय व परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा-3(2) के प्रावधानों के विरूद्ध एवं मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लाघनकर्ताओं को एक वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा। म.प्र. शासन मछली पालन विभाग द्वारा छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है उनको छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

औषधीय पौधों की खेती करना समयानुकूल – मुख्यमंत्री श्री चौहान

किसानों की आय बढ़ाने और जड़ी-बूटियों की आपूर्ति में सहायक होगी देवारण्य योजना ● मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की योजना की समीक्षा

भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि औषधीय पौधों की खेती, किसानों के लिए लाभदायक है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों और स्वास्थ्यगत आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप जड़ी-बूटियों का महत्व और उनकी माँग बढ़ी है। औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित देवारण्य योजना समयानुकूल है। प्रदेश में इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और सक्षम स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कृषकों को चिन्हित किया जाए। किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण, क्षमता विकास और उत्पादों की बिक्री के लिए सही मार्केट लिंकेज स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। आयुर्वेदिक उत्पादों से जुड़ी कम्पनियों की माँग के अनुसार प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करें। किसानों को भी प्र-संस्करण प्रक्रिया से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय पर देवारण्य योजना की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण, श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव वन, श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्री उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव आयुष, श्री प्रतीक हजेला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजीत केसरी बैठक में वर्चुअली सम्मिलित हुए। देवारण्य योजना का क्रियान्वयन वन विभाग के साथ कृषि, उद्यानिकी, आयुष और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

जानकारी दी गई कि प्रारंभिक रूप से योजना का क्रियान्वयन अनूपपुर, नर्मदापुरम, सतना, झाबुआ, डिण्डौरी, बैतूल और सीहोर में किया जा रहा है। अनूपपुर में लेमनग्रास और पॉमारोज़ा, नर्मदापुरम में शतावरी, स्टीविया, मोरिंगा, टुकुमारी और लेमनग्रास से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की योजना है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 21 विकासखंड के 132 स्व-सहायता समूहों द्वारा औषधीय पौधों की फसल ली जा रही है। धार, झाबुआ, मंडला, अनूपपुर, उमरिया, सीहोर, अलीराजपुर और श्योपुर में आँवला, सुरजना, अश्वगंधा, सफेद मूसली, इसबगोल और स्टीविया की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

औषधीय पौधों की मार्केट लिंकेज के लिए डाबर, महर्षि आयुर्वेद, ओमनी एक्टिव, बोटेनिक हेल्थ, नेचुरल रिमेडिस, सिपला और इमामी जैसी कम्पनियों से सम्पर्क किया गया है। कृषकों के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों से उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करने, फेसिलिटेशन केन्द्र से बीज और उत्पाद टेस्टिंग की व्यवस्था तथा पौधों की खेती, औषधियों के विदोहन, प्र-संस्करण, भंडारण, पेकेजिंग और विपणन का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

जल जीवन मिशन के कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों–मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की मिशन की गतिविधियों की समीक्षा

भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन में जारी कार्यों को गति देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुँचाना राज्य शासन की प्रतिबद्धता है। इस तकनीकी युग में कार्य में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध एजेंसियों को उनकी क्षमता के अनुसार ही कार्य आवंटित किया जाए और कार्य की प्रगति पर अधिकारी निरंतर निगरानी रखें। जल जीवन मिशन में संचालित गतिविधियों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए पर्याप्त तकनीकी अमला उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन में जहाँ जल-स्त्रोत कमजोर हों, वहाँ उसे समृद्ध करने के लिए जलाभिषेक अभियान में विशेष प्रयास किए जाएँ। डिजिटल एन्ट्री और इलेक्ट्रानिक तरीके से कार्यों के माप की व्यवस्था को भी सुनिश्चित कराएं।

जानकारी दी गई कि प्रदेश के 51 हजार 585 ग्रामों में जल जीवन मिशन की गतिविधियों का आच्छादन किया जाना है, जिनमें 39 हजार 565 ग्रामों के लिए स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल प्रदाय योजनाओं की प्रगति और पूर्णता की संभावित तिथि की माहवार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

फर्टिलाइजर व कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने निजी क्षेत्र भी सरकार के साथ जुड़ें – श्री तोमर

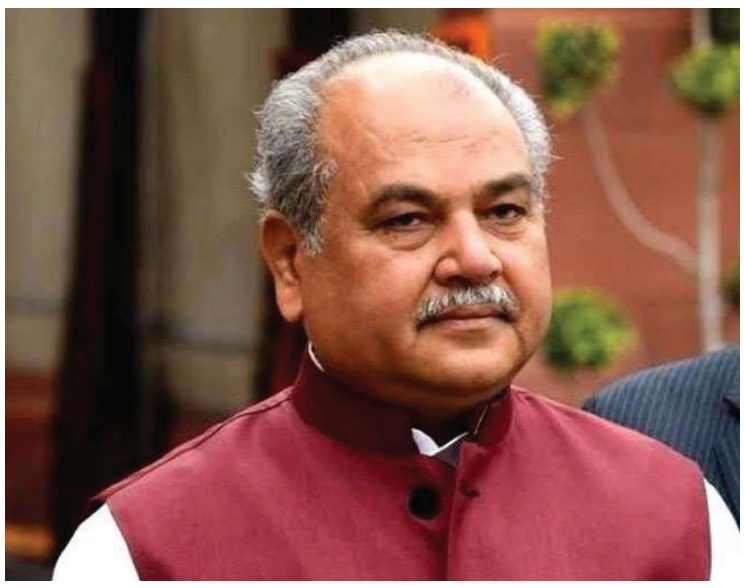

नईदिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि खेती में फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को भी सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। श्री तोमर ने यह बात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) द्वारा आयोजित 11वें एग्रोकेमिकल्स कान्क्लेव को सोलन (हिमाचल प्रदेश) से वर्चुअल संबोधित करते हुए कही।

श्री तोमर ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। "कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए मुनाफा बहुत जरूरी है। उत्पादन में वृद्धि भी बहुत आवश्यक है। देश में दलहन और तिलहन की दृष्टि से अच्छा काम चल रहा है। यह भी जरूरी है कृषि के क्षेत्र में मुनाफा बढ़े तथा फसलोपरांत किसानों को होने वाला नुकसान न्यूनतम हो जिसके लिए कदम उठाने की जरूरत हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। साथ ही सरकार चाहती है कि किसान तकनीक का उपयोग कर महंगी फसलों पर जा सके। फसलों के उत्पादन में एकरूपता आ सके .

श्री तोमर ने कहा कि उद्यानिकी को भी और बढ़ाना चाहिए ताकि हर दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बन सके। "खाद्यान की दृष्टि से हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में हैं। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए हमें कृषि की दृष्टि से विकसित अन्य देशों की ओर भी देखना होगा .

श्री तोमर ने कहा कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने फिक्की जैसे संगठनों से कृषि विकास के लिए मिलकर काम करने की अपेक्षा की।

कार्यक्रम में केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा भी उपस्थित थे।

अमरूद के विपुल उत्पादन के अनुरुप प्र-संस्करण इकाइयाँ लगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान से की निवेशकों ने भेंट

भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में फलोत्पादन और उसके प्र-संस्करण की संभावनाओं को साकार करने में औद्योगिक संस्थान सहयोग करें। विशेष रूप से अनेक जिलों में अमरूद के विपुल उत्पादन को देखते हुए इस तरह की इकाइयाँ लगाई जा सकती हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में उनसे भेंट करने आए मेसर्स पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमेन श्री प्रकाश चौहान, सीईओ सुश्री सचौना और अन्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को संस्थान के पदाधिकारियों ने मध्यप्रदेश में प्रस्तावित नवीन निवेश के संबंध में जानकारी दी। इसके अनुसार मंडीदीप जिला रायसेन में डेरी और फल आधारित पेय पदार्थ रेडी टू सर्व फ्रूट ड्रिंक निर्माण इकाई का विस्तार किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए 2.06 एकड़ भूमि भी संस्थान ने सुरक्षित रखी है। प्रस्तावित पूंजी निवेश 340.86 करोड़ रुपए का होगा और डेढ़ सौ से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा। वर्तमान में पारले समूह खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में मंडीदीप सहित देश में 10 औद्योगिक इकाइयाँ संचालित कर विभिन्न फ्रूट ड्रिंक और डेयरी पदार्थ बना रहा है। वर्ष 1985 से पारले समूह ने इस क्षेत्र में प्रयास किए हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान से जॉन डियर इंडिया लिमिटेड के एमडी श्री शैलेंद्र जगताप और डायरेक्टर श्री मुकुल ने भी भेंट की। औद्योगिक संस्थान के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को प्रदेश में ट्रेक्टर निर्माण और अन्य व्यवसायिक गतिविधियों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय कुमार शुक्ला उपस्थित थे।

अब धान से इथेनॉल बनेगा – श्री गडकरी

इंदौर। पेट्रोल - डीज़ल के लगातार बढ़ते दामों से सभी परेशान हैं। देश को विदेशों से बड़ी मात्रा में ईंधन का आयात करना पड़ रहा है। इन हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले गन्ने से इथेनॉल बनाया ,अब धान से इथेनॉल बनाने की तैयारी है। यह बात केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी ने गत दिनों गोंदिया (महाराष्ट्र) के एक कार्यक्रम में कही।

श्री गड़करी ने कहा कि देश में धान ,चना,मक्का ,गेहूं और शकर का सरप्लस स्टॉक है। किसानों की शिकायत है कि सरकार धान नहीं खरीद रही है। हालात यह है कि पंजाब और हरियाणा के गोदामों में धान रखने की जगह नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण देश का चावल और गेहूं निर्यात हो रहा है,अन्यथा धान उगाने वालों का भविष्य अच्छा नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने भंडारा -गोंदिया जिले के किसानों से तेल वाली फसलों जैसे सोयाबीन,सूर्यमुखी,सरसों और मूंगफली को उगाने का आह्वान किया।

केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार की सोच है कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, ऊर्जादाता भी बने। इसलिए पहले सरकार ने गन्ने से इथेनॉल बनाया। अभी हम पेट्रोल में 20 % इथेनॉल मिला रहे हैं। अभी देश को 450 करोड़ लीटर इथेनॉल मिल रहा है ,जो ज़रूरत की उपलब्धता का आधा ही है। इसलिए सरकार अब धान से इथेनॉल बनाने की तैयारी कर रही है। श्री गड़करी ने जानकारी दी कि रूस के वैज्ञानिकों ने पेट्रोल और इथेनॉल की समान मात्रा लेकर प्रयोग किया तो पाया कि इथेनॉल की कैलोरिक वेल्यू पेट्रोल की तुलना में कम है , अर्थात एक लीटर से केवल 350 मिली लीटर इथेनॉल मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने अपने निवास पर इंडियन ऑइल के चेयरमैन श्री वैद्य के साथ वैज्ञानिक श्री रामकुमार से प्रयोगशाला में नया प्रयोग करने को कहा तो उन्होंने इसे असंभव बताया, लेकिन फिर भी उन्हें प्रयास करने को कहा। तीन माह बाद इंडियन ऑइल ने परीक्षण की सफलता का पत्र भेजा कि यह प्रयोग सफल रहा और अब पेट्रोल और इथेनॉल शत प्रतिशत बराबर है। अब भारत सरकार इसे लागू कर रही है। श्री गड़करी ने कहा कि देश में 10 लाख करोड़ का पेट्रोल -डीज़ल आयात हो रहा है और ऊपर से प्रदूषण भी हो रहा है। इसे देखते हुए अब धान से इथेनॉल बनाने की योजना है। भंडारा -गोंदिया जिले के विकास के लिए देवाड़ा में 600 करोड़ रु का नया विस्तार कर रहे हैं। इसका तीन माह में भूमि पूजन कर कार्य का शुभारम्भ करेंगे। यहां इथेनॉल बनेगा। इसके लिए 600 टन प्रति दिन राइस कट और 1000 टन प्रति दिन राइस स्ट्रा की ज़रूरत पड़ेगी।

बाजरा भारत का सुपर फूड : श्री प्रह्लाद सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में 'भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड' विषय पर राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन उद्योग निकाय एसोचैम ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया। इस सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया।

सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में मोटे अनाज का उत्पादन 2020-21 में बढ़कर 17.96 मिलियन टन हो गया है, जो 2015-16 में 14.52 मिलियन टन था और बाजरा (मोती बाजरा) का उत्पादन भी इसी अवधि में बढ़कर 10.86 मिलियन टन हो गया है।

राष्ट्रीय सम्मेलन में बाजरा के फायदों के बारे में बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि बाजरा देश के सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक रहा है। यह छोटे बीजों से उगाई जाने वाली फसल है जिसे शुष्क क्षेत्रों में या यहां तक कि कम उर्वरता वाली भूमि पर भी उगाया जा सकता है। यही कारण है कि इसे भारत के सुपरफूड के रूप में जाना जाता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फसल का छोटा सीजन होने के कारण, बाजरा लगभग 65 दिनों में छोटे बीज से तैयार होकर काटे जाने लायक फसल के रूप में विकसित हो सकता है। बाजरा फसल की यह विशेषता दुनिया की घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर ठीक से इसे संग्रहित किया जाए तो बाजरा दो साल या उससे अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के पोषण परिणामों में सुधार के लिए बाजरा को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।

भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री मिन्हाज आलम ने दुनिया भर में बाजरा के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में बात की क्योंकि भारत अब दुनिया में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा जो खाद्य विकल्पों में मूल्य सृजन और टिकाऊ उत्पादों को बढ़ावा देगा।

(पृष्ठ 1 का शेष)

वर्तमान प्रतिस्पर्द्धा की दौड़ में....

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सतत् समीक्षा कर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार–अपग्रेडेशन समय–समय पर किया जावे ।

सहकारी बैंक के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का यह दायित्व है कि वे सुरक्षित ऋण वितरण के साथ–साथ वसूली के क्षेत्र में भी निरन्तर सघन प्रयास करें, जिससे प्रदेश के सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में अपार वृद्धि हो और प्रदेश का सहकारी आन्दोलन शासन की मंशा के अनुरूप प्रगति पथ पर अग्रसर हो। अतः निर्धारित समय–सीमा में अपेक्स बैंक मुख्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये वसूली के लक्ष्यों को अर्जित करने के कठोर प्रयास सभी को करना होंगे। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि हमारी समितियों के गोदाम बड़े आकार के बनाये जायें, जिनमें दो कम्पार्टमेंट हो, एक का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये एवं दूसरे का उपार्जन के लिये किया जावे।

अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री पी.एस.तिवारी ने बैठक में सभी से अपेक्षा कि भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त होने वाले नीति–निर्देशों के आधार पर अपेक्स बैंक द्वारा निरन्तर आप सभी को दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं, जिनका अन्तर्मन एवं ईमानदारी से पालन करने के सुनियोजित प्रयास किये जावें ।

संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री अरविंद सिंह सेंगर ने कहा कि समीक्षा बैठक में दिये जाने वाले निर्देशों का निरन्तर/सतत् पालन कराया जाना मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसका अवश्य ध्यान रखा जाये।

श्री बी.एस.शुक्ला, संयुक्त आयुक्त सहकारिता ने अपेक्षा कि सभी प्रकरणों का गहन परीक्षण करने के बाद ही ऋण वितरण किया जावे एवं निर्धारित कानूनी धाराओं के अनुरूप डिफाल्टर होने पर कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे।

बैठक में अपेक्स बैंक के संयुक्त आयुक्त श्री अभय खरे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारीगण श्रीमती अरूणा दुबे, श्री के.के. द्विवेदी, श्री संजय मोहन भटनागर, उपायुक्त सहकारिता श्री उमेश तिवारी, सहायक महाप्रबंधकगण श्री आर.एस. चंदेल, डॉ.रवि ठक्कर, श्री के.टी.सज्जन के साथ अपेक्स बैंक के सभी संभागीय शाखा प्रबंधक, जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सहकारिता विभाग/बैंक के अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कृषि में योगदान पर वेबिनार

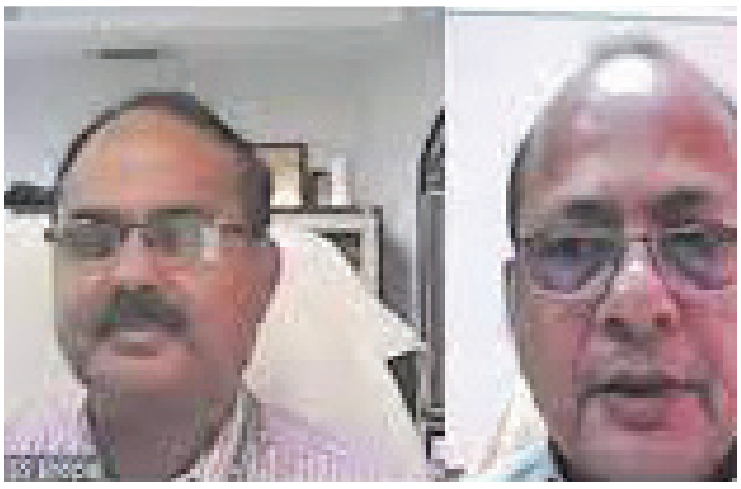

भोपाल। भा.कृ.अनु.परि.-केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के क्रम में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत एक राष्ट्रीय अधिवेशन जिसका विषय 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कृषि में योगदान' का आयोजन गत दिनों संस्थान में ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि डॉ. ए.के.पात्रा, निदेशक, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान,भोपाल उपस्थित थे। मुख्य अतिथि डॉ.पात्रा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कृषि में योगदान विषय पर अपने विचार व्यक्त किये। यह जानकारी डॉ. मनोज त्रिपाठी द्वारा दी गई।

(पृष्ठ 1 का शेष)

आजादी के अमृत .....

साँची के बौद्ध विहार में केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा योग-सत्र में शामिल हुए।

अमृत सरोवर के तट पर हुए योग के विशेष-सत्र

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मध्यप्रदेश में निर्मित हो रहे अमृत सरोवरों के तटों पर भी योग के विशेष-सत्र हुए। इनमें सरोवर के निर्माण में लगे श्रमिक, ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधियों ने मिल कर योग साधना की। इसी प्रकार आँगनवाड़ी केन्द्रों में भी योग-सत्र हुए।

धूपगढ़ की पहाड़ी पर हुई योग साधना

सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर ब्रह्म मुहूर्त में योग के आयोजन शुरू हुए। धूपगढ़ की पहाड़ी के मनोरम स्थल पर पर्यटक, नागरिक एवं स्कूली बच्चों के साथ जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सैलानियों ने भी बढ़-चढ़ कर उत्साह के साथ योग किया। पचमढ़ी में ही बायसन लाज परिसर में भी योग का आयोजन हुआ, जिसमें आयुष विभाग, साडा पचमढ़ी, पर्यटन विकास निगम और पचमढ़ी के स्थानीय नागरिक तथा सैलानियों ने प्रात:काल योग किया। इटारसी के तिलक सिंदूर, सिवनी मालवा के आंवलीघाट, नर्मदापुरम के पावन सेठानी घाट एवं बांद्राभान में भी योग-सत्र हुए, जिनमें योगाचार्यों द्वारा प्रकृति के करीब नागरिकों को योग साधना कराई गई।

स्कूल और कॉलेजों में भी हुआ योग

स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रदेश के सभी स्कूलों में भी सामूहिक योग के आयोजन हुए। साथ ही महाविद्यालयों में भी विद्यार्थियों ने योग साधना की। स्काउट, गाइड, एनसीसी, एनएसएस के युवाओं और शिक्षकों ने भी योग-सत्रों में सहभागिता की। सभी जिलों में सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने भी योग कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई। जन अभियान परिषद के सदस्यों ने भी जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों को जोड़ते हुए योग-सत्र करवाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिलवाया संकल्प

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशवासियों को योग के प्रति प्रोत्साहित करते हुए उन्हें प्रतिदिन योग करने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग करने से न केवल मन प्रसन्न रहता है,बल्कि शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। मेरा सभी से आहवान है कि योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाये। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही नहीं, प्रतिदिन योग करने के लिये समय निकालें।

कृषि तकनीकी स्टार्टअप्स की एक नई लहर

नई दिल्ली । – कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक स्तंभ है, यहां की 54 प्रतिशत आबादी कृषि पर सीधे निर्भर है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा करीब 19 (21) प्रतिशत है। हालांकि भारत में कृषि की पिछले कुछ वर्षों में सतत प्रगति हुई है लेकिन इस क्षेत्र में युवा, ताजा और अभिनव विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया गया।

कृषि तकनीकी से जुड़े स्टार्टअप्स भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। मोदी सरकार द्वारा भारतीय कृषि के समक्ष उत्पन्न- आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, पुराने पड़ चुके उपकरणों के इस्तेमाल, अनुचित संरचना और किसानों की विभिन्न बाजारों का आकलन करने में अक्षमता- जैसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए नीतिगत माहौल प्रदान किए जाने की वजह से पिछले कुछ वर्षों में भारत में कृषि तकनीकी स्टार्टअप्स की एक नई लहर आई है। युवा उद्यमी अब आईटी सेक्टर और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी नौकरियां छोडक़र अपने खुद के स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं। इन युवा उद्यमियों ने अब इस तथ्य को महसूस करना शुरू कर दिया है कि कृषि में निवेश करना बहुत सुरक्षित और लाभकारी व्यापारों में से एक है।

किफायती समाधान

कृषि तकनीकी से जुड़े स्टार्टअप समूची कृषि मूल्य श्रृंखला के समक्ष उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अभिनव विचार और किफायती समाधान सुझा रहे हैं। इन स्टार्टअप्स में इतनी सामथ्र्य है कि वे भारतीय कृषि क्षेत्र के परिदृश्य को बदल सकते हैं और अंतत: किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। यह स्टार्टअप्स और नवोदित उद्यमी किसानों, कृषि सामग्री के डीलरों, थोक विक्रेताओं, फुटकर विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को एक-दूसरे से जोडक़र उनके लिए सशक्त बाजार संपर्क और समय पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करने वाली बीच की कडिय़ां बन सकते हैं।

नई तकनीक के उपयोग की आवश्यकता

कृषि क्षेत्र में आधुनिक नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता है। इजराइल, चीन और अमरीका जैसे देशों ने अपने यहां नई प्रौद्योगिकी की मदद से खेती करने के तरीकों में बड़ा परिवर्तन किया है। इन देशों ने दिखा दिया है कि प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण जैसे हाइब्रिड बीज, सटीक खेती (प्रेसीजन फार्मिंग), डाटा के बड़े पैमाने पर विश्लेषण (बिग डाटा एनालिटिक्स), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), जीओ टैगिंग और सेटेलाइट मॉनीटरिंग,

मोबाइल ऐप और कृषि प्रबंधन सॉफ्टवेयर को खेती की पूरी प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर लागू कर उपज और कृषि से होने वाली आय को बढ़ाया जा सकता है।

ड्रोन्स का इस्तेमाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष फरवरी में कृषि क्षेत्र के लिए देश भर में भारत में निर्मित 100 'कृषि ड्रोन' की शुरुआत की। ये 'कृषि ड्रोन' अपनी अनूठी उड़ानों से खेती की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। सरकार के बजट भाषण में भी फसल के आकलन, भू-रिकॉर्डों के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिडक़ाव के लिए 'किसान ड्रोन्स' के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल फसल या अन्य प्रकार के पेड़-पौधों के स्वास्थ्य की जांच के लिए, खरपतवार (चरस), संक्रमण और कीटों आदि से ग्रस्त खेतों की जांच तथा किसी खेत में रसायनिक उर्वरकों की सटीक जरूरतों का पता लगाने और इस तरह किसान की कुल लागत को कम करने के लिए किया जा सकता है। भारतीय कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की जबर्दस्त क्षमता है, क्योंकि इससे देश की बहुत बड़ी आबादी जुड़ी हुई है। कृषि तकनीकी और कुछ नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर उपज को बढ़ाने, कुशलता लाने और राजस्व में वृद्धि करने का उपाय है। और इससे कृषि प्रक्रिया के सभी आयामों को जोड़ा जा सकता है, चाहे वे कृषि उपयोग में आने वाली वस्तुएं हों या उससे होने वाली उपज।

स्टार्टअप्स दे रहे टिकाऊ समाधान

भारत में बहुत से कृषि तकनीकी स्टार्टअप्स मुख्य रूप से बाजार आधारित हैं, जहां ई-कॉमर्स कंपनियां ताजे और ऑर्गेनिक फल और सब्जियां सीधे किसानों से खरीद कर बिक्री करती हैं लेकिन हाल में बहुत से स्टार्टअप्स ने किसानों की कठिनाइयों के अभिनव और टिकाऊ समाधान प्रदान करने शुरू किए हैं। स्टार्टअप्स अब बायो गैस संयंत्र, सौर ऊर्जा चालित प्रशीतन गृह, बाड़ लगाने और पानी पम्प करने, मौसम का पूर्वानुमान करने, छिडक़ाव करने वाली मशीन, बुआई की मशीन और वर्टिकल फार्मिंग जैसे समाधानों से किसानों को आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

हर किसान तक समाधान पहुंचाने की चुनौती

उम्मीद है कि इंटरनेट उपयोग में वृद्धि, स्मार्ट फोन के उपयोग में वृद्धि, स्टार्टअप्स के उभरने और ग्रामीण इलाकों में की जा रही सरकार की विभिन्न पहलों की वजह से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाने की गति और तेज होगी। कृषि क्षेत्र के ज्यादातर मसलों के प्रौद्योगिकी आधारित समाधान अभी भी हमारे पास हैं लेकिन चुनौती उन समाधानों को देश के सिर्फ एक किसान तक ही नहीं बल्कि हर किसान तक पहुंचाने की है। अब समय आ गया है जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाना होगा ताकि कृषि और किसान समुदाय इससे लाभान्वित हों और इसके बूते भारतीय अर्थव्यवस्था भी तेजी से प्रगति करे।

हल्दी की ये किस्में देती ज्यादा मुनाफा

भोपाल। भूमि –हल्दी की खेती जीवांश युक्त रेतीली या दोमट मटियार मिट्टी में उचित जल निकास की व्यवस्था का होना नितान्त आवश्यक है भारी मृदाओं में, जहां जल निकास का उचित प्रबंध नहीं होता है। वहां पर हल्दी की खेती मेड़ों पर की जाती है हल्दी के लिए पर्याप्त उर्वर भूमि की आवश्यकता होती है इसकी खेती के लिये तालाब के जल द्वारा सिंचित काली मिट्टी उपयुक्त रहती है उन मृदाओं में जहां पर जंगली किस्में उगती पाई जाती हैं, मृदा प्राय: लाल चिकनी या मटियार दोमट होती है इन मृदाओं में पत्तियों की खाद अधिक पाई जाती है, ऊसर या क्षारीय मृदाओं में इसकी खेती सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती लेकिन मृदा में थोड़ी बहुत अम्लीयता का पाया जाना हल्दी के लिये अच्छा रहता है भूमि का पी.एच. मान 5-6 हो और भूमि की सतह कठोर हो।

खेत की तैयारी

मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करने के बाद 3-4 बार देशी हल या कल्टीवेटर चला दें यदि ऐसा संभव नहीं हो तो 5-6 बार देशी हल से जुताई कर दें ढेलों और खरपतवारों को नष्ट कर दें जुताई के बाद पाटा चलायें जिससे खेत में नमी सुरक्षित रहे, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में खेत तैयार करने के उपरांत मेड़ें और नालियां बनाई जाती हैं।

रोपण समय

हल्दी के रोपण का उचित समय अप्रैल एवं मई होता है। हल्दी की बुवाई मानसून के ऊपर निर्भर करती है वर्षा के अनुसार इसकी बोवाई अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक की जाती है।

उपयुक्त किस्में

सीओ1, सुगंधा, सुवर्णा, सुरोमा, सुगना, कृष्ण, बीएसआर।

बीज बुवाई

हल्दी की बुवाई मानसून के ऊपर निर्भर करती है वर्षा के अनुसार इसकी बुवाई अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक की जाती है।

बीज

बीज के लिये हल्दी की गांठें पिछली फसल से ली जाती हैं, बोने के लिये केवल प्राथमिक घनकंद बड़े आकार के और सुविकसित आंखों वाले हो अधिक लम्बा होने पर घनकंदों को छोटे-छोटे टुकड़ों में एक या दो सुविकसित आंखें अवश्य हो।

बीज मात्रा

बीज की मात्रा घनकंदों के आकार व बोने की विधि पर निर्भर करती है। यदि मिलवां फसल बोई जाती है तो 8-10 क्विंटल घनकंद प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होते हैं जबकि शुद्ध बोई जाने वाली फसल के लिए 12-14 क्विंटल घनकंद पर्याप्त होते हैं। घनकंद बोने के लगभग 1 महीने बाद अंकुरित हो जाते हैं जबकि सिंचित भूमि में अंकुरण 15-20 दिन में हो जाता है।

सिंचाई एवं जल निकास

हल्दी की फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है बुवाई से वर्षा ऋतु आरम्भ होने तक 4-5 सिंचाइयों के लिए पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है, यदि मेड़ों में नमी होने पर शीघ्र ही फसल भूमि को ढंक लेती है और वर्षा ऋतु के उपरांत प्रत्येक 20-25 दिन के अंतर पर सिंचाईयां करना लाभप्रद होता है। नवम्बर में पत्तियों का विकास होता है और घनकंद भी मोटाई में बढऩा प्रारंभ हो जाते हैं। इस समय मेड़ों पर मिट्टी चढ़ा देना लाभदायक होता है। हल्दी की फसल में जल्द निकास होना बहुत जरूरी है। खेत में पानी भरे रहने से घनकंदों का विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता उचित जल निकास के लिए 50 से.मी. चौड़ी और 60 से.मी. गहरी नाली बना दी जाती है।

उपज

सिंचित क्षेत्रों में 150-200 क्विंटल और असिंचित क्षेत्रों में 60-90 क्विंटल कच्ची हल्दी प्राप्त होती है। कच्ची हल्दी सुखाने पर 15 से 25 प्रतिशत रह जाती है।

पौध संरक्षण

कीट नियंत्रण- हल्दी की फसल को कीटों से अधिक हानि तो नहीं पहुंचती लेकिन कुछ कीट इसकी फसल को हानि पहुंचाते हैं जो निम्न हैं-

तना बेधक- यह कीट पौधे के नए बढ़ते हुए भागों पर लगता है और इसका रस चूस लेता है जिससे कि पौधा सूख जाता है।

रोकथाम- जिन शाखाओं पर इसका प्रकोप हो गया उनको नष्ट कर दें और नीम का काढ़ा या गौमूत्र का माइक्रोझाइम के साथ मिलाकर छिडक़ाव करें।

राज्य सरकार ने योग आयोग गठन के जारी किये आदेश भोपाल में स्थापित होगा स्वतंत्र कार्यालय

भोपाल : राज्य सरकार ने प्रदेश में योग के प्रति जागरूकता, प्रचार-प्रसार और योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये योग आयोग का गठन किया है। आयोग का एक स्वतंत्र कार्यालय शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में स्थापित होगा, जिसमें एक सचिव, पदेन निदेशक महर्षि संस्कृत संस्थान, दो मल्टीटॉस्किंग स्टॉफ और आवश्यकतानुसार सुरक्षा एवं साफ-सफाई कर्मी (आउट सोर्सिंग) होंगे। आयोग समय-समय पर आवश्यकतानुसार बाह्य स्रोतों से विषय-विशेषज्ञ, व्यावसायिक सेवा एवं सलाहकार सेवा प्राप्त कर सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

आयोग का उद्देश्य

योग आयोग का उद्देश्य यह है कि यह प्रशासकीय विभाग द्वारा गठित निकाय होगा, जो योग संबंधी जागरूकता, प्रचार-प्रसार एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देगा, ताकि बाल्यावस्था से आजीवन योग जीवन का हिस्सा बन सके।

आयोग के कर्त्तव्य

योग आयोग, योग से संबंधित योजना, योग कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं समीक्षा करेगा। योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों को सम्मानित करने एवं पुरस्कार के लिये चयन करेगा। आवासीय एवं गैर-आवासीय योग प्रशिक्षणों का आयोजन करेगा। प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में योग को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिये योग करने हेतु प्रेरित करेगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षणों का आयोजन करेगा। आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा। आयोग का पंजीयन सोसायटी एक्ट के अंतर्गत किया जायेगा। स्कूल शिक्षा विभाग आयोग का प्रशासकीय विभाग होगा, जो आयोग के सुचारु संचालन के नियम बनायेगा।

आयोग की संरचना

स्कूल शिक्षा मंत्री आयोग के पदेन अध्यक्ष, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष पदेन उपाध्यक्ष और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के निदेशक पदेन सचिव होंगे। साथ ही राज्य शासन द्वारा योग के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले 5 अशासकीय सदस्य मनोनीत होंगे। आयोग में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय, खेल एवं युवा कल्याण, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास एवं पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के प्रतिनिधि शासकीय सदस्य होंगे। आयोग में आवश्यकता अनुसार नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल केडेट कोर, स्काउट-गाइड एवं अन्य समूहों के सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकेगा। अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग क्लास संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित

भोपाल। जिला संयोजक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये संचालित बालक, कन्या उत्कृष्ट छात्रावास राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर एवं जीरापुर में विषयवार कोचिंग क्लास के संचालन हेतु शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय पढाने वाले शिक्षक, शिक्षिकाओं से आवेदन पत्र 07 जुलाई, 2022 तक आमंत्रित किए गए है। कक्षा 9वी एवं कक्षा 10वीं में कोचिंग देने वाले शिक्षक, शिक्षिकाओं के लिये संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा कक्षा 11वी एवं 12वी की विषयवार कोचिंग के लिये संबंधित विषय के लिए स्नातकोत्तर में 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं के लिए विषयवार नियुक्त शिक्षक, शिक्षिकाओं को उसी दिन कक्षावार अलग-अलग विषयवार कालखण्ड में पढायेंगे। कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र की कक्षाएं गणित समूह के साथ एवं जीव विज्ञान समूह के लिए कामन रहेगी। अग्रेंजी विषय की कक्षाएं तीनों समूह (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित एवं जीव-विज्ञान तथा कॉमर्स) के लिए कामन रहेगी। कक्षा 11वीं एवं 12वी के लिए विषयवार नियुक्त शिक्षक, शिक्षिका उसी दिन कक्षावार एवं विषयवार अलग-अलग कालखण्ड में पढायेंगे। उत्कृष्ट छात्रावासों में विषयवार कोचिंग हेतु नियुक्त शिक्षक, शिक्षिकाओं को 300 रूपये प्रति कालखण्ड एवं अधिकतम 6,000 रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। उच्च शैक्षणिक योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जायेगी। उत्कृष्ट छात्रावासों में विषयवार कोचिंग क्लास में पढाने हेतु इच्छुक शिक्षक, शिक्षिकाऐं अपने आवेदन पत्र जिसमें फोटो कक्षा 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य शैक्षणिक योग्यता जो भी हो की सत्यापति प्रतियों के साथ संलग्न कर 07 जुलाई, 2022 तक सायं 5:00 बजे कार्यालयीन समय में जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग जिला राजगढ़ के कक्ष क्रमांक-126 एवं संबंधित उत्कृष्ट छात्रावासों में जमा कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन पत्र उत्कृष्ट छात्रावासों के अधीक्षको से प्राप्त किये जा सकते है। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

पूसा सुगंध 5 धान की किस्म

नई दिल्ली। पूसा सुगंध 5 धान की किस्म – विवरण: 2004 में सीवीआरसी द्वारा बासमती उगाने वाले क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर के लिए वैरायटी जारी की गई थी। मुख्य विशेषताएं: उत्तरी भारत में बहु फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त एक अर्ध-बौनी उच्च उपज वाली सुगंधित चावल की किस्म। इसमें अतिरिक्त लंबे अनाज और उत्कृष्ट खाना पकाने की गुणवत्ता है। इसमें बिखरने की सहनशीलता होती है। यह 120-125 दिनों में पक जाती है और इसकी औसत उपज 5.5-6 टन प्रति हेक्टेयर होती है।

मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से होगा शुरू

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से – मध्यप्रदेश की पंचदश विधानसभा का द्वादश सत्र सोमवार दिनांक 25 जुलाई से प्रारंभ होकर शुक्रवार दिनांक 29 जुलाई तक चलेगा। राज्यपाल के आदेशानुसार इस आशय की अधिसूचना मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने जारी की है। विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री ए पी सिंह ने बताया कि 25 जुलाई से प्रारंभ होने वाले पांच दिवसीय सत्र में सदन की कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान शासकीय कार्य संपादित किए जाएँगे।

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित,
भोपाल द्वारा संचालित
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध
शीघ्र आयें प्रवेश पायें
PGDCA
(योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण)
कुल फीस 9100/-
DCA
(योग्यता -10 +2 उत्तीर्ण)
कुल फीस 8100/-
संपर्क :-
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र
ई- 8/77 शाहपुरा ,त्रिलंगा ,भोपाल
फोन : 0755-2926160 , 2926159
मो. 8770988938 , 9826876158 Website-www.mpscu.in
Web Portal-www.mpscuonline.in
Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006
फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053
Email - ctcindore@rediffmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।